(b) if so, what measures are being taken in this direction;

(c) whether some of the State Governments have reduced the voting age to 18 for the local administration elections; and

(d) if so, which are those States?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) and (b). The question whether the miimum voting age for elections to Lok Sabha and to the Legislative Assemblies of States should be reduced from 21 years to 18 years has been under Government's consideration, as part of the proposals for comprehensive electoral reforms. As the proposals involve consideration of important matters of policy, Government are likely to take some more time to take decisions thereon, including the proposal for reducing the voting age.

(c) and (d) According to the information received from the State Governments of Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Kerala, Himachal Pradesh and Madhya Pradesh have reduced the minimum voting age for Panchayat elections from 21 years to 18 years and Andhra Pradesh, Gujarat, Kerala, Rajasthan and West Bengal have reduced the minimum voting age for elections to Municipal Corporations/Municipalities from 21 years to 18 years.

Functioning of Special Courts

*8. SHRI N.E. HOHO Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Special Courts which were functioning during Janata Party regime have been held illegal recently; and

(b) if so, the details regarding arguments and the number of cases withdrawn as a result thereof?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) and (b). Mr. Justice M. L. Jain, Judge, Special Court No. 2 in his judgement dated 15-1-1980 on certain criminal miscellaneous applications filed in Case No. 1 of 1979 and Case No. 2 of 1979 held that the Notification dated 30th May, 1979 creating and establishing the Special Court and the declarations and designations to try the aforementioned cases, were not made in accordance with the provisions of the Constitution and were therefore, of no effect and conferred no jurisdiction on the Court. He accordingly held that the Special Court was precluded from proceeding further in these cases. Shri Justice M. S. Joshi, Judge, Special Court No 1 in his judgements dated 14-2-1980 (in Case No. 2 of 1979) and 18-2-1980 (in Case No. 1 of 1979) gave a similar finding in respect of the Notification dated 30th May, 1979 creating and establishing the Special Courts

None of the cases that were instituted in or transferred to the Special Courts under section 6 of the Special Courts Act, 1979, has been withdrawn.

देश में बिजली की कमी तथा बिहार में रबी की फसल पर इसका प्रभाव

*9 श्री विजय कुमार यादव : क्या ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समूचे देश में बिजली की अभूतपूर्व कमी है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि बिजली की देशव्यापी कमी के कारण बिहार राज्य में, विशेष कर नालन्दा जिले में, रबी की फसल पर सबसे अधिक बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ग) क्या सरकार का विचार बिहार में बिजली का संकट दूर करने के लिए कोई कार्यवाही करने का है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) कई राज्य इस समय विद्युत् की कमी का सामना कर रहे हैं। विद्युत् की कमी के मुख्य कारण ये हैं :—

(1) कुछ राज्यों में मानसून से वर्षा न होना, जिसके परिणामस्वरूप जल विद्युत केन्द्रों से जलविद्युत कम उपलब्ध होना।

(2) मांग में वृद्धि होना। राज्यों में वर्तमान अभूतपूर्व सूखा की स्थिति होने तथा फसलों से स्वरूप में परिवर्तन होने के कारण कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से अधिक वृद्धि होना।

(3) बढ़ती हुई भार मांग को पूरा करने के लिए प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता कम होना।

(4) कुछ ताप विद्युत केन्द्रों में कोयले की कमी के कारण तथा कुछ केन्द्रों के घटिया अनुरक्षण के कारण तथा विद्युत केन्द्रों का कार्य-निष्पादन अपेक्षाकृत घटिया होना।

(ख) बिहार भी विद्युत की कमी का सामना कर रहा है। इसके कारण हैं ताप विद्युत केन्द्रों की कम उपलब्धता तथा उड़ीसा की जल विद्युत प्रणाली से किसी प्रकार की सहायता न मिलना। उक्त प्रणाली आपातकालीन परिस्थितियों में पूर्वी क्षेत्र की लगभग 100 मेगावाट तक सहायता करती थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि रबी की फसल प्रभावित न हो विभिन्न राज्यों में कृषि कार्यों के लिए यथासंभव अधिकतम विद्युत सप्लाई करने के लिए हर संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं। लोड शेडिंग की स्थितियों में कृषि सेक्टर की सप्लाई पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तथापि, यह कहना कठिन है कि बिहार राज्य में, विशेषरूप से नालन्दा जिले में, रबी की फसल पर केवल विद्युत की कमी के कारण सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है।

(ग) बिहार राज्य में विद्युत की उपलब्धता सुधारने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। हाल ही में चालू किए गए पतरातू के 110–110 मेगावाट के दो यूनिटों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने हेतु, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लि० और इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०, कोटा के वरिष्ठ इंजीनियरों का एक दल बिहार में भेजा जा रहा है। ऊर्जा मंत्री ने कलकत्ता में एक बैठक बुलाई थी और बिहार राज्य बिजली बोर्ड के तकनीकी सदस्य को अनुदेश दिए हैं कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विशेषज्ञों को तथा ऊर्जा मंत्रालय के परामर्शदाताओं की सेवाएं प्राप्त करें। बिहार राज्य बिजली बोर्ड को यह भी अनुदेश दिए गए हैं कि पतरातु निर्माणाधीन 110–110 मेगावाट के दो यूनिटों की और बरौनी के 110–110 मेगावाट के दो और यूनिटों को तथा स्वर्णरेखा जल विद्युत केन्द्र के दूसरे यूनिट को, जिसके शीघ्र ही चालू होने की आशा है, शीघ्र चालू किया जाए।

Installation of Captive Generating Sets by Cement Units

*10. SHREE F. H. MOHSIN: Will the Minister of ENERGY AND IRRIGATION AND COAL be pleased to state:

(a) the particulars of the applications for installation of captive generating sets pending in his Ministry submitted by the various Cement Units in the private sector;

(b) whether the delay caused in processing them and issuing the licences has resulted in considerable fall in cement production leading to its import against foreign exchange, and

(c) the action which he proposes to take to expedite the disposal of these applications and issue licences to the parties concerned and grant them priority in the matter of import of the plant?

THE MINISTER OF ENERGY AND IRRIGATION AND COAL (SHRI A B A GHANI KHAN CHOUDHURI): (a) Two applications have been received in the last two years in this Ministry from Cement Units in the Private Sector for installation of captive generating capacity. They are (i) Mysore Cements for 10 MW capacity and (ii) Associated Cemment Companies for 25 MW capacity.

In the case of Mysore Cements, they applied for a captive plant of 10 MW, which proposal was examined in consultation with the various authorities concerned. In the meantime, after obtaining clearance from Karnataka State Electricity Board, as required under law, the Company has installed a 10 MW set purchased from Maharashtra State Electricity Board which has been commissioned on 26-12-1979. Their application for